नईदुनिया

संपादकीय

आग से धधकता लॉस एंजेलिस

लॉस एंजेलिस में जंगल की बेकाबू आग फैलने और भारी जन-धन की क्षति ने साबित किया है कि दुनिया की नंबर एक महाशक्ति भी कुदरत के रौद्र के सामने बौनी ही साबित हुई है। जंगल की आग ने भड़कने के बाद कई शहरी इलाकों को चपेट में ले लिया। खरबों रुपये की संपत्ति और प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने के अलावा करीब दो लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। आलीशान बंगलों व सरकारी संरचना तथा नागरिक सुविधा के साधनों के स्वाह होने के साथ करीब बारह लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब दो लाख लोगों को घर-बार छोड़कर जाने के लिये तैयार रहने को कहा गया है। दमकल विभाग व सुरक्षा बलों की तमाम कोशिशों के बावजूद आग बेकाबू है। लोग असहाय होकर अपनी जीवन भर की पूंजी को स्वाह होते देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते तल्ख होते मौसम से हालात और खराब होने की आशंका जतायी जा रही है। आग के बाद का जो मंजर नजर आ रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बम गिराया गया हो। विडंबना यह है कि आपदा में अवसर तलाशने वाले कुछ लोग खाली कराये गए घरों में लूटपाट से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हॉलीवुड हिल्स इलाके में करीब साढ़े पांच हजार से अधिक इमारतों के नष्ट होने की खबर है। कई नामी फिल्मी हस्तियों के घर, व्यावसायिक इमारतें व सार्वजनिक संस्थान आग की भेंट चढ़े हैं।

अमेरिका के इतिहास में यह जंगल की आग सबसे भयावह साबित हुई है। चिंता की बात यह है कि इलाके में हाल-फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है, जिससे जंगल की आग जल्दी काबू में आ सकती। एक बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति ठप होने व पानी की आपूर्ति में बाधा संकट को और बढ़ा रही है। लोगों की सुरक्षित स्थानों में जाने के लिये अफरा-तफरी से जगह-जगह ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। पानी का दबाव कम होने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी आ रही है। दरअसल यह आग लॉस एंजेलिस के उत्तरी भाग में लगी, जिसने बाद में कई बड़े शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं व सूखे मौसम के कारण आग ज्यादा भड़की है। सूखे पेड़-पौधे तेजी से आग की चपेट में आ गए। हालांकि, आग लगने का ठोस कारण अभी तक पता नहीं चला है। हकीकत है कि जंगलों में 95 फीसदी आग इंसानों द्वारा ही लगायी जाती है। वैसे जलवायु परिवर्तन प्रभावों के चलते बदले हालात में अब पूरे साल आग लगने की आशंका बनी रहती है। बारिश की कमी से सूखा और तेज हवाएं आग में घी का काम करती हैं। मौसम का गरम रहना व बारिश की कमी भी आग के लिए ज्वलनशील परिस्थितियां बनाते हैं। इस बार आग को भड़काने में सौ मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली सेंटा एना हवाओं की भी बड़ी भूमिका रही है। इस बार ये हवाएं असामान्य रूप से बहती रही हैं। इलाके में राख के बारीक कणों व धुएं की चादर के कारण स्थानीय स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित की गई है।

मप्र नए आयाम छूने तैयार, शहडोल को लगे विकास के पंख

ऋतुपर्ण दवे

निश्चित रूप से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह सोच उनकी दूरदर्शिता ही है जो उन्होंने प्रदेश के इस दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थित आखिरी संभाग की खूबी को न केवल पहचाना बल्कि मूर्त रूप देने का प्रयास किया। शहडोल को विकास की गति देने में उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की भी महती भूमिका है। निश्चित रूप से मध्यप्रदेश का यह 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपने आम में मिशाल होगा जो बेमिशाल होगा। बस एक कसक प्रकृति के अकूत वरदानों से भरे जनजातीय, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के इलाके की रह गई है कि काश संभाग का नाम नर्मदा संभाग होता और अनूपपुर जिले का नाम मां नर्मदा के नाम रेवाखंड जिला तथा उमरिया का नाम विश्व प्रसिध्द राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ के नाम होता तो यह सोने में सुहागा जैसा होता। विश्वास है कि देर-सबेर यह भी होगा।

हर कहीं विकास की संभावनाएं होती हैं। मध्यप्रदेश में भी अपार संभावनाएं हैं। संसाधनों व प्राकृतिक वरदान के चलते शहडोल में तो और भी ज्यादा हैं। जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के बावजूद खनिज तथा दूसरे प्राकृतिक संसाधन यहां भरपूर हैं। जहां एक ओर कोयले का अकूत भण्डार है तो दूसरी ओर संभाग में तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बड़े बिजली उत्पादन केन्द्र हैं। अमरकण्टक थर्मल पॉवर प्लाण्ट, चचाई, संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र बिरसिंहपुर पाली तो जैतहरी में मोजर बेयर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसे अब, हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। शहडोल से करीब सिंगरौली भी वह जगह है जहां कोयला और बिजली दोनों का उत्पादन होता है। कहने का तात्पर्य यह कि विन्ध्य में यदि सबसे ज्यादा विकास की संभावनाएं कहीं हैं तो वह है शहडोल। कभी शहडोल का अकेला जिला आज संभाग में तब्दील हो अपने पुराने स्वरूप को नए नाम से पा तो चुका है। लेकिन बावजूद इसके अपने महत्व और उपलब्धियों को लेकर नए नाम और पहचान के लिए संघर्षरत है।

यह सच है कि भाजपा शासन के कार्यकाल के दौरान ही शहडोल को उसकी प्राकृतिक उपलब्धियों और प्रचुरता के चलते नया आयाम मिला। आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर शहडोल देश और विदेश को अपनी ओर इन्ही खूबियों के चलते आकर्षित कर रहा है। 16 जनवरी को हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए अब तक 20 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं। इधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी इसको लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि उद्योग लगाने के लिए जो निवेशक मध्यप्रदेश आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देंगे। निवेशकों की सुविधा के लिए हर जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर प्रारंभ किए गए हैं। जिला कलेक्टरों को इनका नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बनाई गई हैं। इसमें मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर है।

जहां तक शहडोल में उद्योग की संभावनाओं की बात है तो यहां पर एक ओर जहां कोयले की प्रचुरता है तो दूसरी बड़े-बड़े पॉवर प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा रिलायंस का सीबीएम प्रोजेक्ट पहले ही शहडोल को देश में अलग मुकाम दिला चुका है। जमीन की भी कोई कमीं नहीं है। शहडोल के अलावा बेहद करीब कोलफील्ड और ऊर्जा के हब के रूप में सिंगरौली भी है जो किसी तोहफे जैसा है। निश्चित रूप से किसी भी उद्योग के लिए ऊर्जा और जगह की खासियत अहम होती है। दोनों मामलों में शहडोल बेहद सौभाग्यशाली है। इतना ही नहीं कभी यहां एशिया की दूसरी सबसे बड़ा कागज कारखाना ओरियन्ट पेपर मिल बनी जो आज भी पूरी गति से संचालित है। कागज उद्योग की और भी संभावनाओं के साथ यहां पर खनिज प्रसंस्करण, गैस आधारित उद्योग और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में भी निवेश की भी अपार संभावनाएं हैं।

निश्चित रूप से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह सोच उनकी दूरदर्शिता ही है जो उन्होंने प्रदेश के इस दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थित आखिरी संभाग की खूबी को न केवल पहचाना बल्कि मूर्त रूप देने का प्रयास किया। शहडोल को विकास की गति देने में उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की भी महती भूमिका है। निश्चित रूप से मध्यप्रदेश का यह 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपने आम में मिशाल होगा जो बेमिशाल होगा। बस एक कसक प्रकृति के अकूत वरदानों से भरे जनजातीय, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के इलाके की रह गई है कि काश संभाग का नाम नर्मदा संभाग होता और अनूपपुर जिले का नाम मां नर्मदा के नाम रेवाखंड जिला तथा उमरिया का नाम विश्व प्रसिध्द राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ के नाम होता तो यह सोने में सुहागा जैसा होता। विश्वास है कि देर-सबेर यह भी होगा।

इतना ही नहीं शहडोल की उपलब्धियां अपने आप में विश्व व्यापी है। यहां से ही देश की उस नदी 'नर्मदा' का उद्गम होता है जिसके दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। वहीं सोन का भी उद्गम यहीं से होता है। अमरकण्टक शहडोल के पर्यटन उद्योग को चार चांद लगाने के लिए अलग धार्मिक, आध्यात्मिक केन्द्र जैसी पहचान भी रखता है। इस पवित्र नगरी के कायाकल्प के लिए भी राज्य सरकार पुरजोर कार्य कर रही है। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ेगा बल्कि मध्यप्रदेश के इस अनूठे प्राकृतिक स्थल को लोग बार-बार देखने आते हैं और आते रहेंगे। विश्व विख्यात नर्मदा और सोन का उद्गम अमरकण्टक वैसे भी दुनिया में अलग स्थान रखता है। जहां अमरकण्टक से निकली नर्मदा गुजरात के लिए वरदान कहलाती है तो सोन बिहार के लिए लाइफ लाइन से कम नहीं है।

अमरकण्टक की मेकल, विन्ध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों की सुन्दरता और दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जहां प्राकृतिक हरियाली, कीमती जड़ी-बूटियां, प्राचीन तप स्थलियां और पहाड़ों की सुन्दरता देखते ही बनती है। जैसे-जैसे शहडोल औद्योगिक रूप लेगा निश्चित रूप से अमरकण्टक की वादियां और पुण्यता भी इसके विकास को चार चांद लगाएंगी। वहीं विश्व विख्यात बांधवगढ़ भी शहडोल के गौरव को बढ़ाता है। दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। इसीलिए बांधवगढ़ अम्बानी परिवार को भी खूब भाया।

शहडोल से सटा लालपुर भी दशकों तक विन्ध्य का जाना माना निजी हवाई अड्डा था। यहां देश के बड़े उद्योगपति और कागज कारखाना अमलाई के मालिक अपने निजी विमान से उतरा करते थे। बाद में देश के कई प्रधानमंत्री भी इस जगह पर उतरे। आज मध्यप्रदेश शासन के भावी हवाई अड्डों में शहडोल के इसी लालपुर का नाम है जहां पर 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आए थे और पकरिया गांव के ग्रामीणों से न केवल संवाद किया बल्कि खटिया पर बैठकर देशी पत्तल में जनजातीय क्षेत्र के श्री अन्न कोदो का भात, कुटकी की खीर और दूसरे देशी व्यंजन खाए थे। आज शहडोल अपने नए रूप और अधिकार को पाने के लिए बांहे बिछाए सबके स्वागत को तैयार है तो लालपुर को इंतजार है कि शहडोल के विकास को हवाई जहाज के पंखों से गति मिले ताकि देश-विदेश के लोग सीधे शहडोल पहुंच सकें। वाकई शहडोल बदल रहा है और गढ़ने को तैयार है विकास के नित नए आयाम।

राजनैतिक पूंजी गंवा चुकी 'आआपा' के समक्ष किला बचाने की चुनौती

विकास सक्सेना

नया दल इन दुर्गुणों से मुक्त रहकर नए प्रकार से राजनीति करते हुए देश को वैकल्पिक राजनीति का मॉडल देगा। उस समय ऐलान किया गया कि इस दल में 'हाई कमान कल्चर' नहीं होगा, सभी निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। पार्टी नेताओं को भ्रष्ट आचरण से दूर रखने के लिए पार्टी का अपना लोकपाल होगा जो सभी नेताओं की निगरानी करेगा। बड़े-बड़े आदर्शों के साथ शुरू हुई आम आदमी पार्टी ने चंद महीनों के भीतर खुद को पारंपरिक राजनीति के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में पहली बार जनता की अदालत में पहुंची आम आदमी पार्टी के 28 उम्मीदवारों को लोगों ने विधानसभा पहुंचा दिया। सत्ता की चाह में बच्चों की कसम और सभी आदर्शों को भुलाकर अरविन्द केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली।

दिल्ली की सत्ता पर पिछले दस साल से काबिज आम आदमी पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से जन्मे इस राजनैतिक दल के नेता खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। जिस राजनैतिक जमा पूंजी के साथ इस राजनैतिक दल का गठन किया गया था, बीते एक दशक में ही उसके नेताओं ने इसे पूरी तरह गंवा दिया है। पार्टी की स्थापना के समय जो उच्च नैतिक मानदंड और आदर्श स्थापित किया गए थे वे दूर-दूर तक पार्टी नेताओं के व्यवहार में नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल विपक्ष के साथ- साथ अपने पूर्व सहयोगियों के भी निशाने पर हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान अण्णा हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। उस समय टू जी स्पेक्ट्रम, कामनवेल्थ गेम्स, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी और कोयला घोटाले जैसे लाखों करोड़ रुपये के घपलों के समाचार लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रहे थे। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुए घोटालों के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट और न्यायालय के आदेशों से लोगों को लगने लगा था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग या तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त या भ्रष्टाचारियों को उनका संरक्षण प्राप्त है। लगातार दूसरी बार देश की सत्ता पर काबिज होने से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का दंभ चरम पर था। भ्रष्टाचार से जुड़े हर सवाल के जवाब में वे एक ही बात कहते नजर आते थे कि 2009 के आम चुनाव में दूसरी बार सत्ता सौंप कर देश की जनता ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में समाजसेवी अण्णा हजारे के नेतृत्व में इण्डिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन की सिर्फ एक मांग थी कि देश में जनलोकपाल बनाया जाए।

असीम शक्तियों से सम्पन्न यह जनलोकपाल देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। इसी समय योग गुरू बाबा रामदेव ने भी विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन शुरू किया। जिसे सरकार ने निर्ममता पूर्वक कुचल दिया। देश की जनता राजनेताओं, बड़े कॉरपोरेट घरानों और नौकरशाही की दुरूभि संधि से दिनों-दिन बढ़ते भ्रष्टाचार को अपने दैनिक जीवन में महसूस कर रही थी। जनलोकपाल का जो खाका अण्णा हजारे के आंदोलन के समय पेश किया गया उसे देख कर लोगों ने महसूस किया कि इससे भ्रष्टाचार की समस्या पर काफी हद तक काबू किया जा सकेगा। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस के नेताओं ने जनलोकपाल बनाने की मांग का उपहास करते हुए आंदोलन से जुड़े नेताओं को खुद राजनीति में आकर इस तरह का कानून बनाने की चुनौती दी। अण्णा आंदोलन को देशभर में मिले व्यापक जनसमर्थन और तत्कालीन सत्ताधारी दल कांग्रेस के विरुद्ध तैयार हो रहे जनमत से उत्साहित आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं ने राजनैतिक क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को साफ करने के लिए लिए स्वयं इस दलदल में उतरने की योजना बनाई। हालांकि अण्णा हजारे इस आंदोलन से जुड़े लोगों के राजनीति में उतरने के विचार से सहमत नहीं थे। वैकल्पिक राजनीति के नए विचार के साथ अरविन्द केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी आदि ने एक नया राजनैतिक दल बनाने की योजना तैयार की और इसे नाम दिया गया- आम आदमी पार्टी। इस राजनैतिक दल की औपचारिक घोषणा के लिए दिन चुना गया 26 नवम्बर 2012 का ताकि देश की जनता को भारत के संविधान के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का सीधा संदेश दिया जा सके। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को ही देश के संविधान को स्वीकृति प्रदान की थी। इसी समय पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए अरविन्द केजरीवाल ने कहा था 'हम आम आदमी हैं। अगर वामपंथी विचारधारा में हमारे समाधान मिल जायें तो हम वहां से विचार उधार ले लेंगे और अगर दक्षिणपंथी विचारधारा में हमारे समाधान मिल जायें तो हम वहां से भी विचार उधार लेने में खुश हैं।' आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय सबसे ज्यादा जोर देते हुए कहा गया कि अब तक देश की सत्ता पर काबिज रहे राजनैतिक दलों में तमाम प्रकार के दुर्गुण आ गए हैं।

नया दल इन दुर्गुणों से मुक्त रहकर नए प्रकार से राजनीति करते हुए देश को वैकल्पिक राजनीति का मॉडल देगा। उस समय ऐलान किया गया कि इस दल में 'हाई कमान कल्चर' नहीं होगा, सभी निर्णय सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। पार्टी नेताओं को भ्रष्ट आचरण से दूर रखने के लिए पार्टी का अपना लोकपाल होगा जो सभी नेताओं की निगरानी करेगा। बड़े-बड़े आदर्शों के साथ शुरू हुई आम आदमी पार्टी ने चंद महीनों के भीतर खुद को पारंपरिक राजनीति के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में पहली बार जनता की अदालत में पहुंची आम आदमी पार्टी के 28 उम्मीदवारों को लोगों ने विधानसभा पहुंचा दिया। सत्ता की चाह में बच्चों की कसम और सभी आदर्शों को भुलाकर अरविन्द केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। इसके बाद एक-एक करके उन सारे आदर्शों को तिलांजलि दे दी गई जिनकी बात 26 नवम्बर 2012 को की गई थी।

पार्टी के अधिकांश संस्थापक सदस्यों प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास आदि ही नहीं बल्कि पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास तक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को सादगी पूर्ण जीवन की बात कहते हुए छोटे मकान, छोटी कार और सीमित सुरक्षा की नसीहत देते थे लेकिन सत्ता में आते ही आआपा नेता उन सभी सुख-सुविधाओं को भोगते नजर आ रहे हैं जिसे लेकर वे राजनेताओं की तीखी आलोचना किया करते थे। खासतौर पर अरविन्द केजरीवाल पर कोरोना काल में अपने सरकारी आवास की मरम्मत पर 33 करोड़ रुपये खर्च करने के आरोप लगे। लाखों रुपये के पर्दे, टॉयलेट और टायल्स आदि को लेकर चर्चा में आया उनका आवास शीशमहल के तौर पर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अरविन्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन समेत पार्टी के तमाम नेता और मंत्री महिला उत्पीड़न, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल की हवा खा चुके हैं। जहां तक हाईकमान संस्कृति की बात है तो ऐसा लगता है कि अरविन्द केजरीवाल अब पार्टी के स्थायी राष्ट्रीय संयोजक हो चुके हैं। उनके शब्द पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम आदेश है और मुख्यमंत्री पद के एकमात्र दावेदार भी वही होंगे।

आजकल

विदेशी मुद्रा भंडार में आ रही गिरावट

विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। पिछले दो महीने से एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गुजरा, जब भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दर्ज न की गई हो। इसके समांतर डालर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत भी लगातार गिर रही है। रुपया छियासी के पार पहुंच गया है। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी फेडरल की नीतियों में बदलाव, डालर की मजबूती और भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की भारी निकासी बताई जा रही है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार ने रुपए की गिरती कीमत को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी शुरू की थी। मगर वह कारगर उपाय साबित नहीं हो सका। अब दोनों में समांतर गिरावट दर्ज होने लगी है। यह विदेशी निवेश आकर्षित करने, कर्ज पर ब्याज के भुगतान, जरूरी आयात आदि के मद्देनजर गंभीर चिंता का विषय है। रुपए की कीमत गिरने से आयात महंगा हो जाता है, पर्यटन, विदेशी शिक्षा आदि पर खर्च बढ़ जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में छीजन बढ़ने से विदेशी कर्ज के ब्याज में भुगतान को लेकर चिंता गहराने लगती है।

विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी इस बात का भी संकेत है कि अपेक्षित विदेशी निवेश नहीं आ पा रहा है। निवेशकों का भरोसा कमजोर हो रहा है, इसलिए वे सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी की जो तस्वीर पेश की जा रही थी, वह अब धुंधली पड़ने लगी है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की विकास दर नीचे बनी हुई है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। निर्माण क्षेत्र भी कमजोर होता जा रहा है।

पिछले बारह-तेरह वर्षों से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। निर्यात लगातार हिचकोले खा रहा है और घरेलू बाजार में रौनक लौट नहीं पा रही। महंगाई पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। इसके बावजूद, विचित्र है कि सरकारें मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करने की होड़ में शामिल हैं। वे विदेशी कर्ज लेकर इन्हें चलाने का प्रयास कर रही हैं। यह असंतुलन खत्म हुए बिना विदेशी मुद्रा भंडार के भरने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत

अमिताभ पाण्डेय

नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति दुनिया भर के लिए आदर्श उदाहरण बन रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से प्रयास किया जा रहे हैं । इन प्रयासों के कारण भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में भारत की कुल क्षमता 209.44 गीगावॉट हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हर वर्ष जिस तरह प्रगति देखी जा रही है वह प्रशंसनीय है।

ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत वर्ष 2030 के पहले ही 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 के बीच की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उल्लेख किया है। यह वृद्धि स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और इसके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है। ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहा यह हरित परिवर्तन हमारे भविष्य को बेहतर बना रहा है।

रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि : दिसंबर 2024 तक, भारत की कुल

नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट की तुलना में 15.84 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2024 के दौरान जोड़ी गई कुल क्षमता 28.64 गीगावाट थी, जो वर्ष 2023 में जोड़े गए 13.05 गीगावाट की तुलना में 119.46 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाती है।

सौर और पवन ऊर्जा में वृद्धि: वर्ष 2024 में, सौर ऊर्जा 24.54 गीगावाट की वृद्धि के साथ इस वृद्धि का नेतृत्व करेगी, जो इसकी संचयी स्थापित क्षमता में वर्ष 2023 में 73.32 गीगावाट से वर्ष 2024 में 97.86 गीगावाट तक 33.47 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पवन ऊर्जा ने भी इस विस्तार में योगदान दिया है। वर्ष 2024 में अतिरिक्त 3.42 गीगावाट स्थापित होने से कुल पवन क्षमता बढ़कर 48.16 गीगावाट हो गई, जो 2023 से 7.64 प्रतिशत की वृद्धि है।

जैव ऊर्जा और लघु जल विद्युत ऊर्जा में वृद्धि : बायोएनर्जी ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इसकी स्थापित क्षमता दिसंबर 2023 में 10.84 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2024 में 11.35 गीगावाट हो गई है, जो 4.70 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। छोटी पनबिजली परियोजनाओं में भी वृद्धि देखी गई, जिनमें स्थापित क्षमता वर्ष 2023 में 4.99 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2024 में 5.10 गीगावाट हो गई, यह 2.20 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहल की है। यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये प्रभावशाली आंकड़े भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करते हैं।